अब निर्यात का हब बनेगा लखनऊ

एक्शन प्लान तैयार, जिला स्तरीय निर्यात समिति की बैठक में दी योजना की जानकारी

माई सिटी रिपोर्टर

बैठक में उद्यमियों के साथ डीएम डॉ. सूर्यपाल गंगवार। -संवाद

लखनऊ। राजधानी को निर्यात का हब बनाने का एक्शन प्लान तैयार हो गया है। इसे लेकर शनिवार को कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय निर्यात समिति की बैठक बुलाई गई।

इसमें उद्यमियों, किसानों व व्यापारियों को डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब के बारे में सरकार व निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के माध्यम से तैयार की गई जिला निर्यात योजना की जानकारी दी गई।

उपायुक्त उद्योग मनोज चौरसिया ने बताया कि ओडीओपी कार्यक्रम के जरिये प्रमुख निर्यात क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए निर्यातकों से योजनाओं का ऑनलाइन लाभ प्राप्त करने के लिए कहा गया।

इस दौरान ओडीओपी उत्पाद चिकनकारी एवं जरी जरदोजी के निर्यातक मंसूर नदीम लारी, विभू दीक्षित और मे. त्रिवेणी चिकन की ओर से जापान तथा काम्प्रिहेन्सिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट से संबंधित अन्य देशों में निर्यात की संभावनाओं के बारे में बताया गया।

मंसूर नदीम लारी ने भारत सरकार की ओर से शुरू किए गए एमआईसीई (मीटिंग, इन्क्रियेटिव, कान्फरेन्स एवं एक्जीविशन) के प्रोत्साहन से उत्पादों की ब्रांडिंग तथा बिक्री में वृद्धि पर बल दिया। इस पर डीएम डॉ. सूर्यपाल गंगवार ने एमआईसीई ब्यूरो के गठन के लिए प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा। बैठक में निर्यातक अकरम बेग ने आम की खेती, भिंडी, मिर्च और केला के गल्फ क्षेत्र में निर्यात को लेकर आ रही समस्या की जानकारी दी। डीएम ने उन्हें डीपीआर तैयार कर समिति को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बेग ने आम तथा दूसरे फल व सब्जियों के लिए मैंगो पैक हाउस की स्थापना के बाद निर्यात में हुई बढ़ोतरी की जानकारी दी।

हालांकि, उन्होंने खेत से पैक हाउस तक कोल्ड चेन न होने से हो रही परेशानी का भी जिक्र किया। इस पर डीएम ने नाबार्ड के माध्यम से कोल्ड चेन के लिए प्रपोजल तैयार कराने के निर्देश दिए।

सुलझा एमएसएमई विवाद, किया भुगतान

लखनऊ। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के भुगतान के निस्तारण को लेकर शनिवार को मंडलीय फैसिलीटेशन काउंसिल की बैठक हुई। इसमें 21 मामले रखे गए। तीन में एक करोड़ 42 लाख, 37 हजार 286 करोड़ का भुगतान करने का आदेश दिया गया। तीन अन्य में आठ लाख से ज्यादा का भुगतान सुलह-समझौते से कराया गया। बैठक में संयुक्त उद्योग आयुक्त कंचन सुबोध, लघु उद्योग भारती की प्रतिनिधि रीता मित्तल आदि थे। (माई सिटी रिपोर्टर)

फाइलों के दबाव से मुक्त होगा कलेक्ट्रेट, एक क्लिक पर काम

माई सिटी रिपोर्टर

कलेक्ट्रेट और राजस्व विभाग के सभी कार्यालयों को ई-ऑफिस से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू

ईमेल से अधिकारियों को भेजी जाएंगी फाइलें, पारदर्शी होगी व्यवस्था

लखनऊ। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कलेक्ट्रेट और राजस्व विभाग के सभी कार्यालयों को ई-ऑफिस से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शनिवार को इस संबंध में हुई बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि कलेक्ट्रेट, विकास भवन और सभी तहसील ई-ऑफिस से जुड़ेंगे। इससे एक क्लिक पर काम होगा।

सभी फाइलें ईमेल से संबंधित अधिकारी को भेजी जाएंगी। अधिकारी ईसिग्नेचर से इनका निस्तारण करेंगे। इससे लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण होगा और कलेक्ट्रेट, विकास भवन व सभी तहसीलें फाइलों के दबाव से मुक्त होंगी। डीएम डॉ. सूर्यपाल गंगवार ने बताया के ई-ऑफिस प्रणाली में हर अधिकारी व कर्मचारी को व्यक्तिगत डिजिटल सिग्नेचर दिए जाएंगे। इसके लिए एजेंसी ने कलेक्ट्रेट और विकास भवन में कैंप लगाया है।

इस प्रणाली के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता है, उनका सर्वे कराया जा रहा है। कलेक्ट्रेट के सभी पटलों पर कंप्यूटर व स्कैनर उपलब्ध करा दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि फाइल को स्कैन कर सीधे संबंधित को ईमेल पर भेजा जाएगा। सभी कर्मचारियों को हिंदी टाइपिंग की जानकारी जरूरी है। इसके लिए एक माह का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। मंगलवार तक सभी कर्मचारियों को लॉगिन उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इसके बाद ई-ऑफिस प्रणाली पर काम करने की ट्रेनिंग दी जाएगी।

कलेक्ट्रेट, विकास भवन और तहसीलों में एक-एक लाइब्रेरी बनाकर इससे संबंधित पुस्तकें भी रखी जाएंगी। एडीएम वित्त एवं राजस्व राकेश कुमार सिंह ने बताया कि इस प्रणाली से पारदर्शी काम होगा। किसके पास कितनी फाइलें लंबित है, इसकी जानकारी भी आसानी से मिल जाएगी। कोई भी कर्मचारी बिना वजह फाइल नहीं रोक पाएगा। शासन की ओर से तय समय में ई-ऑफिस प्रणाली शुरू कर दी जाएगी।